राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(A)(16)आर.बी./2021/42 दिनांक : 4 जनवरी, 2022

—: कार्यवाही विवरण :—

राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण की समन्वय समिति की बैठक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 11:00 बजे राजभवन, जयपुर में आयोजित हुई, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री, श्री बी.डी. कल्ला, चिकित्सा मंत्री, श्री परसादी लाल मीणा, कौशल, खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री, श्री अशोक चांदना एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र सिंह यादव एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रशासनिक विभागों के अधिकारीगण तथा समस्त कुलपतिगण उक्त बैठक में उपस्थित रहे।

1. बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची **संलग्नक—1** पर संलग्न है।

2. सर्वप्रथम सचिव, राज्यपाल ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं बैठक की रूपरेखा से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रारम्भिक उद्बोधन हेतु निवेदन किया।

3. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि सभी कुलपतिगण टीम भावना से कार्य करें। सभी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में परस्पर विचार—विनिमय करें। विश्वविद्यालय में भी कुलपति अपने विभिन्न विभागों के आचार्यों से और छात्र प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद के कार्यक्रम रखें। स्ववित्त पोषण के साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी कैसे हों, पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, संचालन और उनकी पढ़ाई, संकायों से जुड़ी नियुक्तियों और अन्य व्यवस्थाओं में सभी विश्वविद्यालय एकरूपता की नीति अपनाएं। शिक्षा ऐसी हो जिससे विद्यार्थी निरंतर सीखने के लिए उत्सुक रहें। विश्वविद्यालय अच्छे नवाचारों, विद्यार्थियों के हित से जुड़े मुद्दों के साथ ही गुणवत्ता से जुड़े शोध कार्यों में निरंतरता रखते हुए सभी कार्य करें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय अपने यहां नवीनतम शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करें, जिससे विद्यार्थी बहुत सारी किताबों के संदर्भ से एक पुस्तक तैयार करने की सोच की बजाय अपने स्वयं के अनुभव, अध्ययन से मौलिक स्थापनाओं की ओर प्रवृत्त हों। विश्वविद्यालय के कुलपतियों से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने यह भी आग्रह किया कि सभी कुलपति समन्वय रखते हुए अपने यहां वर्षों से चल रहे पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के प्रयास करें।

4. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के उद्बोधन पश्चात उनकी अनुमति से सचिव, राज्यपाल द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं एजेण्डा बिन्दुओं पर कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया।

5. प्रो. ए.के. गहलोत द्वारा विश्वविद्यालयों में Resource Generation किस प्रकार से किया जाए, के संबंध में Resource Generation & Technological Interventions in SFU's विषय पर PPT का प्रस्तुतिकरण किया गया **(संलग्नक–2)**। इस संबंध में सचिव, राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण को 10 साल तक की Resource mapping तैयार कर राजभवन को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. बैठक में समस्त 16 एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं तद्नुसार लिये गये निर्णय की सूची **संलग्नक–3** पर संलग्न है।

7. बैठक में समस्त 16 एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरांत प्रशासनिक विभागों के अधिकारीगण एवं माननीय मंत्रियों द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया है :–

- **विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग** – विश्वविद्यालयों को वित्त विभाग से जो भी अपेक्षाएं है उन्हें पूरा करने के प्रयास किए जायेंगे साथ ही वित्तीय समस्याओं के संबंध में वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

- **प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग** – जमीन एवं पेंशन संबंधी प्रकरण के संबंध में उचित समाधान हेतु follow up किया जायेगा।

- **अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग** – विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि राज्य सरकार पर आर्थिक निर्भरता कम करने हेतु Self Finance Course को ज्यादा से ज्यादा बढावा दे। उससे छात्र भी ज्यादा आकर्षित होंगे। छात्र संख्या बढ़ने से विश्वविद्यालयों की आर्थिक सुदृढता बढ़ेगी। साथ ही भामाशाहों से अधिक से अधिक संपर्क कर आर्थिक संसाधन जुटाने के प्रयास करें तथा विश्वविद्यालयों की जमीन को विक्रय के संबंध में सोच–समझकर निर्णय लेवें।

- **माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री** – कुलपति एवं कुलसचिव के मध्य विवाद के संबंध में मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार पूर्ण रूप से मदद को तैयार है। विश्वविद्यालयों में राजनीतिकरण अच्छी बात नहीं है। वित्तीय संसाधनों के बारे में विश्वविद्यालय प्रदेश के बजट सत्र से पहले अपनी योजना बनाकर भिजवाये, ताकि राज्य सरकार के स्तर पर उनका निराकरण कराया जा सके।

- **माननीय शिक्षा मंत्री** – विश्वविद्यालयों द्वारा 25 वर्ष का मास्टर प्लान बनाया जावे। जिसमें शुरू के दो वर्ष, अगले 5 वर्ष एवं इसी प्रकार से आगे के वर्षों की योजना तैयार कर उसका पुनरीक्षण किया जाए। विश्वविद्यालयों की आर्थिक सुदृढता के लिए Alumni, भामाशाहों, औद्योगिक घरानों एवं राज्य सरकार से

अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाए। वर्तमान समय में निजी विश्वविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों से अधिक फीस वसूल कर रहे हैं। इस हेतु सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले वे छात्र जो फीस देने की स्थिति में है उनसे फीस ली जावें एवं जो छात्र नहीं दे सकते है, उनकी फीस माफ करके राहत दी जावें। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी फिजूल खर्चों को रोका जाए तथा जो विषय एवं शोध समय के अनुसार अनुपयोगी हो गए हैं, उन्हें बंद किया जाए एवं समयानुकूल शोध एवं पाठ्यक्रम को बढावा दिया जाए। पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में सुझाव दिया कि उनकी अनुदानित जमीनों पर समयानुसार नई फसलों की खेती एवं शोध कर नए बीजों को विकसित किया जाए। जिससे उनकी आमदनी बढे एवं किसानों को भी लाभ मिले। विश्वविद्यालयों के लिए UGC की तर्ज पर State Regulation Authority बनाई जानी चाहिए।

संविदा कर्मियों की मांग जिस विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, वित्त विभाग द्वारा उन्हें स्वीकृत किया जाना चाहिए। पुराने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने चाहिए। Board of Studies में ऐसे कोर्स पास होने चाहिए जिससे विद्यार्थी अखिल भारतीय सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके जिससे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके। विश्वविद्यालयों को UGC से अधिक से अधिक Grant प्राप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए। शोध पर पर्याप्त ध्यान दिया जाकर उसकी पहचान की जानी चाहिए।

- **माननीय चिकित्सा मंत्री** – प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के खुलने से राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब हुई है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय बंद हो जायेंगे। विश्वविद्यालयों के अधिकारी विश्वविद्यालय के कार्यों में रूचि नहीं लेंगे तो विश्वविद्यालयों की स्थिति दिनो–दिन ओर ज्यादा दयनीय होती जायेगी। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय का सुझाव है कि इस संबंध में कैबिनेट में चर्चा हो एवं मंत्री महोदय द्वारा माननीय बी.डी. कल्ला जी जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, को निवेदन किया गया कि इस संबंध में सारी समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाकर इन समस्याओं का निदान कराया जावे। विश्वविद्यालयों में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के पदस्थापन हेतु कोई पॉलिसी बनाई जावे। विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश की धरोहर हैं। इनके संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है। अंत में मंत्री महोदय द्वारा कुलाधिपति महोदय को भी निवेदन किया गया कि प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते विश्वविद्यालयों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की जावे।

- **माननीय कौशल, खेल एवं युवा मामलात राज्य मंत्री** – माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रथम सत्र में निम्नानुसार अपने विचार प्रकट किये–

विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र–छात्राओं से प्राप्त आवेदनों का Data, DoIT के माध्यम से Singal Portal बनाकर उसमे आवेदकों से उनके विकल्प (Choice) भरवाकर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जावें, जिससे विद्यार्थी को वास्तविक Admission की सटीक जानकारी मिल पायेगी एवं प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी एवं प्रदेश में एक समान शुल्क लागू हो सकेगा। वर्तमान समय में आयोजित ऑनलाईन कक्षाओं के कारण विद्यार्थियों को ऑनलाईन खेलों की लत लग गई है, जिसके कारण आउटडोर खेलों में उनकी रूचि निरन्तर कम होती जा रही है जिसके कारण उनकी दिनचर्या एवं स्वास्थ्य में आमूल–चूल परिवर्तन होने की आशंका है। इस वर्ष प्रदेश में अन्तर–जिला, अन्तर–राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, निकट भविष्य में प्रदेश में ग्रामीण ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता कराने का विचार है, इस हेतु 27 लाख खिलाड़ियों को शामिल करने का लक्ष्य है।

8. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समापन संबोधन में निम्न निर्देश / घोषणा की गई :–

- नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें, जिनमें प्रारम्भ से ही कौशल विकास की प्राथमिकता हो, जिससे युवा पढ़ाई के साथ–साथ कार्य भी कर सकेंगे जिससे उन्हे आर्थिक संबल मिलेगा।
- विश्वविद्यालय शैक्षणिक / अशैक्षणिक रिक्त पदों से संबंधित प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग में भिजवायें। शैक्षणिक / अशैक्षणिक पदों की रिक्तियों को भरने संबंधी कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र पूर्ण की जाये। शैक्षणिक रिक्तियां तत्काल पूर्ण करने की आवश्यकता है, जिससे विश्वविद्यालय को NAAC एवं अन्य संबंधित ग्रेड़िग में फायदा हो।
- प्रमुख रूप से कृषि विश्वविद्यालयों, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों जिनमें पेंशन संबंधी समस्या है, उनके समाधान हेतु विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें, जिससे Resource Generate हो। तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय की Assests को बेचकर Resource Development करें, साथ ही जिस प्रकार महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा अपनी जमीन पर कम लागत में अधिक उत्पादन कर Resource Generate किया है वैसा अन्य कृषि विश्वविद्यालय भी इस माध्यम से Resource Generate कर सकते हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे नवाचार किये जाये, जिससे विश्वविद्यालयों में Resource Generate हो सके।
- समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा जनवरी 2022 तक SUMS को लागू किया किया जाये।
- विश्वविद्यालयों द्वारा Alumni Association एवं Alumni से सम्पर्क कर भव्य Alumni सम्मेलन आयोजित किये जायें ताकि उनसे अपेक्षित सहयोग लिया जा

सके एवं विश्वविद्यालय में संसाधन बढाये जा सकें। इसके अतिरिक्त औद्योगिक घरानों व कम्पनियों से संपर्क कर विश्वविद्यालयों को गोद लेने व उनके CSR Fund से सहायता हेतु प्रयास किए जाएं।

- राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में कुलसचिव/वित्त नियंत्रक की नियुक्ति लगभग 2 वर्ष के लिए की जाये, अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाये।
- विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे शोध/नवाचार/गुणवत्ता विकसित की जाये कि वहां का छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जावे।
- समस्त विश्वविद्यालय, परिसर में सोलर प्लांट विकसित करें, जिससे बिजली बिल लागत कम की जा सके एवं अधिक उत्पादन होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आस–पास ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करवायी जा सके।
- समस्त विश्वविवद्यालय, परिसर में Rain Water Harvesting System विकसित करें, जिससे वर्षा जल को उपयोग में लिया जा सके।
- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये मदार गांव में किये गये कार्य/नवाचारों की तरह अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी अपने गोद लिये गांव में कार्य किये जावें।
- कुलाधिपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि समस्त युवाओं को भारतवर्ष के संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संविधान पार्क/संविधान स्तम्भ, मार्गदर्शन ग्रंथ है, इनके विश्वविद्यालयों में स्थापित होने से विद्यार्थियों में संविधान के प्रति रूचि बढ़ेगी। अतः समस्त विश्वविद्यालयों को परिसर में संविधान पार्क/संविधान स्तम्भ बनाया जाना अति–आवश्यक है। इस हेतु शेष विश्वविद्यालय रूचि लेकर शीघ्र यह कार्य पूर्ण करवाएं।
- आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्थानीय/राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की लड़ाई में किस–किस ने भाग लिया एवं किस–किस ने योगदान दिया के संबंध में प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा कृतियों/कार्यक्रमों/संगोष्ठी/ कार्यशालाओं के माध्यम से अभियान चलाकर युवाओं को जानकारी से अवगत करावें, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग का भी सहयोग लिया जा सकता है।

9. बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(16)आर.बी. / 2021 / 43 दिनांक : 5 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रो. ए. के. गहलोत, सदस्य, राज्यपाल सलाहकार बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

प्रमुख सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(16)आर.बी. / 2021 / 44 दिनांक : 5 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन यथाशीघ्र आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, युवा मामलात एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।

प्रमुख सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(16)आर.बी. / 2021 / 45 दिनांक : 5 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निदेशक (जनजाति कल्याण) एवं संयुक्त सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा), राजभवन, जयपुर।
4. उप सचिव (द्वितीय), राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, (IT), राजभवन जयपुर को राजभवन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

संलग्नक 1

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 27th December, 2021
at 11.00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur

Attendance Sheet

S.N.	Name	Designation	Mobile No.	Signature
1.	राजेन्द्र सिंह यादव	राज्य मंत्री	7073187474	[signature]
2.	डॉ० बुलाकीदास कल्ला	मंत्री, स्कूल शिक्षा	98292-55855	[signature]
3.	Ashok chandna	state minister	9772898888	[signature]
4.				
5.	परसादी लाल मीणा	चिकित्सा मंत्री	9414036121	[signature]
6.	Pawan. K. Goyal	ACS, School & Sanskrit Education	9414024500	[signature]
7	Dinesh Kumar	Pr. Secretary, Agriculture	9414021555	[signature]
8.	Naresh Thakral	Spl. Secy (Fin)	9414070555	[signature]
9.	NL Meena	Secretary Higher & Tech Edu.	9414775228	[signature]
10.	BHANUPRAKASH.Y	Secretary, LSEE	9413301800	[signature]
11.	Shuchi Tyagi	Commissioner, college edu	9414082800	[signature]
12.	Rajeev Jain	V.C. University of Raj	9414163049	[signature]
13.	P.C. Trivedi	V.C., J.N.V.U, Jodhpur	9414248524	[signature]
14.	Amarika Singh	V.C. MLSU	9621246077	[signature]
15.	Ratanlal Godara	VMOU-KOTA	9558095921	[signature]
16.	Anil Chhikara	MDS University Ajmer	9415180307	[signature]
17.	DR. Neelima Singh	University of Kota	9425339973	[signature]
18.	DR. I.V. TRIVEDI	GGTU, BANSWARA	9001997557	[signature]
19.	Prof. J. P. YADAV	RRBM- ALWAR	9414362125	[signature]

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 27th December, 2021
at 11.00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur

Attendance Sheet

S.N.	Name	Designation	Mobile No.	Signature
20.	Prof RK Bhakar	V.C., MSBU Bharatpur	9837035081	[signature]
21.	Prof Sandeep Tandon	Pro VC, RUHS	9829065148	[signature]
22.	Prof. Ajay Kumar Sharma	VC, MBMU	9928082027	[signature]
23.	Dr J.S. Sandhu	VC, SKNAU, Jobner	9582898978	[signature]
24.	Dr B.R Choudhary	VC, AU, Jodhpur	9414265317	[signature]
25.	Dr. D.C. Joshi	VC, AU, Kota	9909020668	[signature]
26.	Dr. N.S. RATHORE	VC, MPUAT, Udaipur	9414166561	[signature]
27.	Prof. R.P. Singh	VC, SKRAU, Bikaner	9412723066	[signature]
28.	Prof Ambarish S. Vidyarthi	VC, BTU, Bikaner	7902008999	[signature]
29.	Prof. R.A. Gupta	VC, RTU, KOTA	941405286	[signature]
30.	ANULA MAURYA	VC, JRRSU	9810353171	[signature] 27.12.21
31.	Prof. Abhimanyu Kumar	V.C. DSRA Uni. Jodhpur	8800543828	[signature]
32.	ओम थानवी	कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता वि., जयपुर	9873710777	[signature]
33.	Bhagirath Singh	V.C PDUSU	9829266377	[signature]
34.	DR DEV SWARUP	VC, Dr Bhimrao Ambedkar Law Univ. Jaipur	9871490304	[signature]
35.	DR ALOK TRIPATHI	VC, Police University Jodhpur	9414040411	[signature]
36.	Dr. Kavita Singh	Director TW & SSG	9664257012	[signature]
37.	Prof (Dr.) Col. A.K. Gahlot	Member, Governor's Advisory Board	9414138211	[signature]
38.	Govind Ram Jaiswal	Principal OSD to Hon'ble Governor	8800589095	[signature]

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 27th December, 2021
at 11.00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur

Attendance Sheet

S.N.	Name	Designation	Mobile No.	Signature
39.	SUNIL SHARMA	Joint Secretary Medical Education	9829015899	[signature]
40.	Sonila Mathur	Addl. Chief Vigilance Commissioner - Home	8302788889	Sonila
41.	Rajan Lal Bunjan	Nodal officer Sports Se	9950204702	[signature]
42.	Dr R K Singh	Dean & Chairman Faculty RAJUVAS Bikaner	9414430084	[signature]
43.	Dr. P. C. Bhati	Additional Director Deptt. of Animal Husb.	9414779785	[signature]
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				

राज्य विश्वविद्यालयों में संसाधन सृजन एवं तकनीकी अंतःक्षेप

Resource Generation and Technological Interventions in SFUs

Prof. (Dr.) Col. A. K. Gahlot

Founder Former Vice-Chancellor,

RAJUVAS, Bikaner (Raj) 334003

Contact : 09414138211; ajeygahlot@gmail.com

राज्य के विश्वविद्यालयों को स्तरीय कैसे बनाएं?

सुलभ वित्तीय संसाधन

शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार में तकनीकी अंतःक्षेप

ई–गवर्नेन्स द्वारा संतुलित एवं रियल टाइम गवर्नेन्स

मजबूत एवं कुशल नेतृत्व

स्वत्व अधिकार

शैक्षणिक स्वतंत्रता

प्रत्येक स्तर पर प्रतिभाओं के लिए प्रतिबद्धता

संसाधन सृजन

Everywhere, Academic institutions are being asked to bear an increasing part of their budgets through tuition and student fees, funds raised by consultation and selling research-based patents, technologies, products etc. and other resource generating activities.

यह सत्य है कि राज्य पोषित विश्वविद्यालयों को राजकीय सहायता अति आवश्यक होती है।

दूसरी ओर कई संस्थानों के पास अपना कॉर्पस फंड भी होता है।

सुलभ वित्तीय संसाधनों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय आर्थिक संसाधनों के विकास पर ध्यान दे।

क्या और कैसे करें ?

विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर से सुझाव लेना

रिसोर्स जनरेशन सेल बना कर लगातार संसाधन सृजन की मॉनिटरिंग करना

आय व्यय को सुगमता से करने हेतु प्रशासनिक सुधार करना

कुछ आंकड़ों का समय समय पर विश्लेषण करना

आय के स्रोतों का वर्गीकरण कर वर्तमान स्रोतों का सुदृढिकरण एवं नवीन स्रोतों को तलाशना

आय बढाने वाले स्टाफ एवं इकाइयों को प्रोत्साहित करना

अन्य सफल विश्वविद्यालयों की प्रणालियां अपनाना

कार्पस फंड सृजित करना

महत्वपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण करें

- Budget from various sources
- Salary : Contingency ratio
- State share vs Total budget
- Teacher : Student ratio
- Cost of production of Graduate, Post-graduate, Ph.D. etc.
- Year wise comparison of important expenditures
- Classify and analyze income sources
- Prepare financial road map for next at least 10 years

Conclusions

- वित्तीय संसाधनों का लगातार विश्लेषण करते रहें।
- आय के स्रोतों की निरंतर तलाश करते रहें।
- संसाधन सृजन को वित्तीय प्रबंधन का लक्ष्य बनाएं।

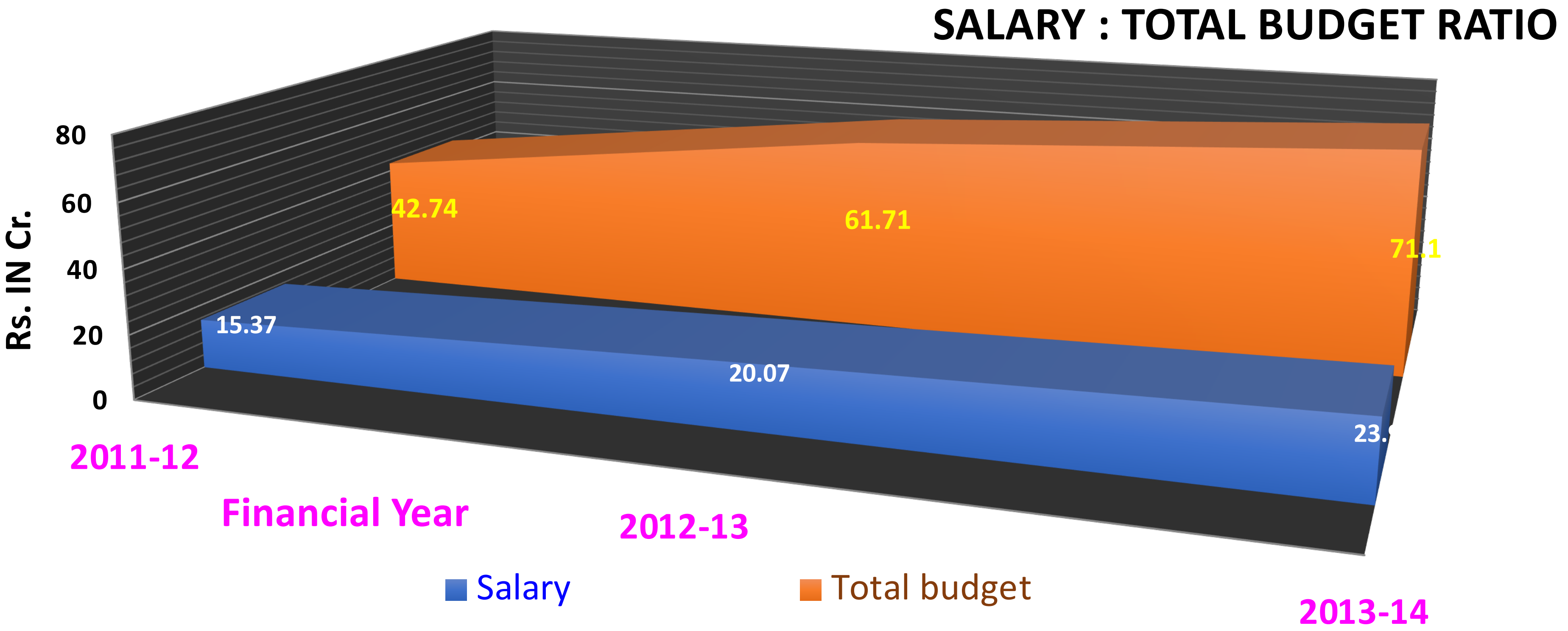
SALARY : TOTAL BUDGET RATIO
80
60
40
20
0
Rs. IN Cr.
42.74
61.71
71.1
15.37
20.07
23.
2011-12
Financial Year
2012-13
2013-14
Salary
Total budget

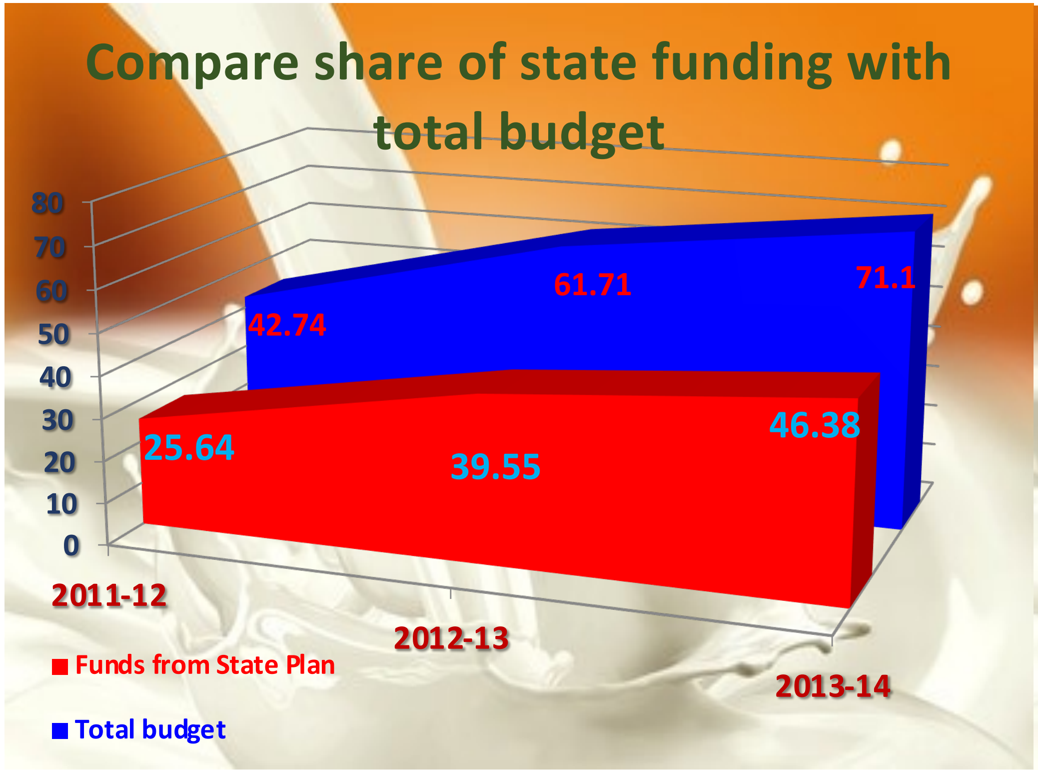
Compare share of state funding with total budget
80
70
60
50
40
30
20
10
0
42.74
61.71
71.1
25.64
39.55
46.38
2011-12
2012-13
2013-14
Funds from State Plan
Total budget

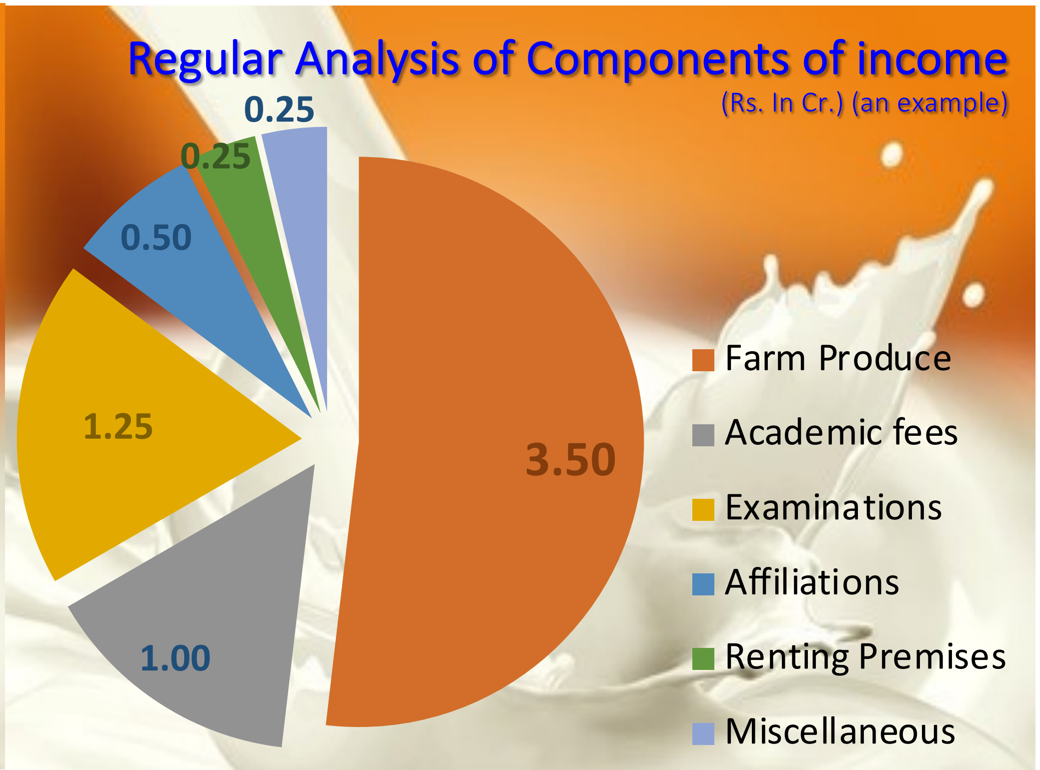
Regular Analysis of Components of income
(Rs. In Cr.) (an example)
0.25
0.25
0.50
1.25
1.00
3.50
Farm Produce
Academic fees
Examinations
Affiliations
Renting Premises
Miscellaneous

तकनीकी अंतःक्षेप

Technical Interventions

Changing Teaching Technologies

- We’ve all seen the black and white images of the one-room schoolhouse.
- Students sit in perfect rows that face a teacher who’s writing on a chalkboard.
- Up until the last decade, our classrooms haven’t drastically differed from those 100-year-old images.
- We are so fortunate to be living and teaching in a time of rapid educational change.
- Instead of personal student chalkboards, a number of students now have access to electronic tablets.
- Many teachers can now use Smartboards instead of dry-erase boards.
- The limits of the central textbook have transcended the limitless information gathered online.

The Digital Approach

Technology-Aided Instruction and Intervention (TAII)

Any instruction or intervention in which the learner's goals are primarily achieved with technology as the central feature.

[Odom et al. (2015)]

eLMS is one such example

ICT Eases Inclusion in Education

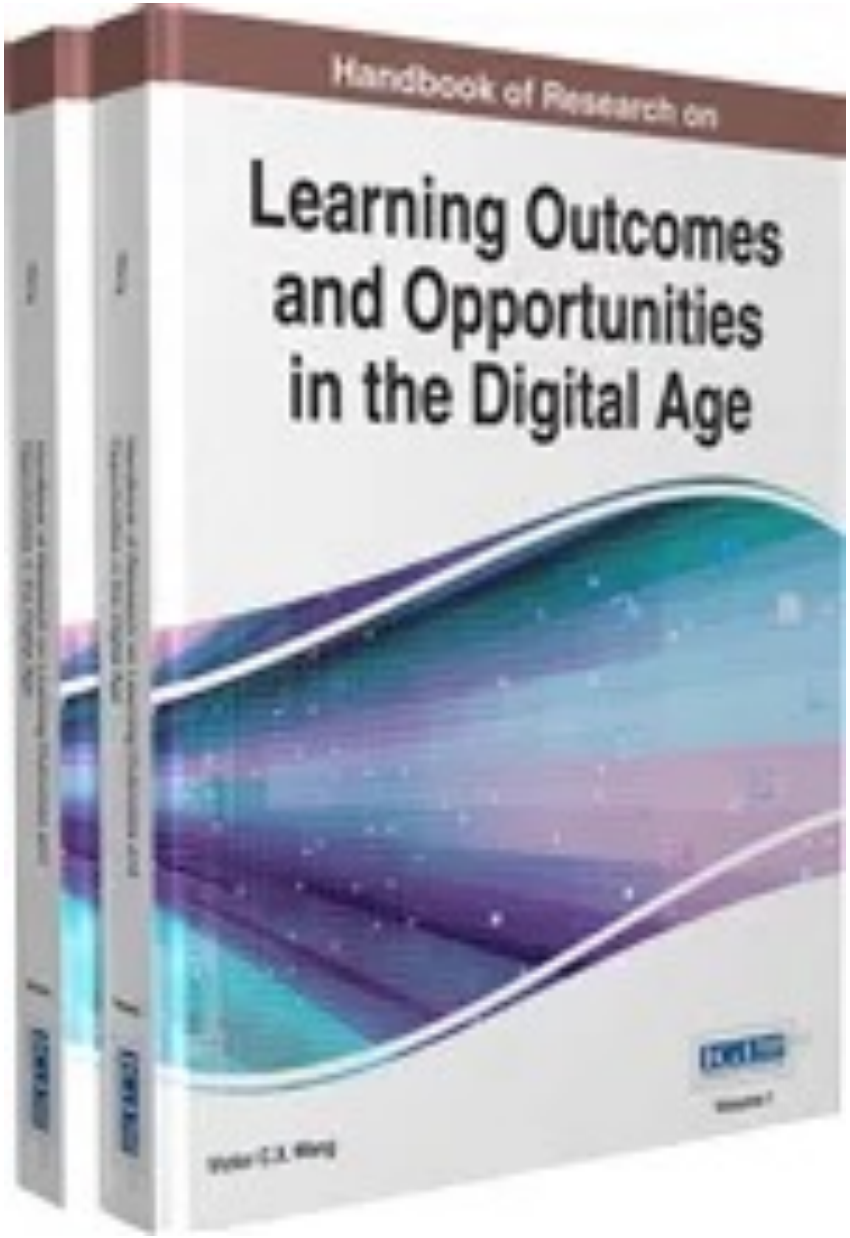

- ICT could be a particularly valuable tool for people with disabilities; these tools can improve these individuals' quality of life, reduce social exclusion, and increase social participation.
- Inclusive education involves focusing on the individual needs of learners, helping them to overcome any barriers that may prevent them from reaching their potential.
- Through the extensive use of ICT in education, it becomes possible to meet the specific needs of different groups of students, including students with special needs.

Ellen Boeren (University of Edinburgh, UK): Handbook of Research on Learning Outcomes and Opportunities in the Digital Age Copyright: © 2016

Assistive Technologies

an example of Inclusion

- **ICTs that are used to support children, young people, and adults with disabilities, are commonly referred to as assistive technologies (AT), although there is no one single internationally accepted definition for this term.**

- **The British Assistive Technology Association (BATA), a social enterprise that focuses on AT for inclusion in education, defines AT as any item, equipment, hardware, software, product or service which maintains, increases or improves the functional capabilities of individuals of any age, especially those with disabilities, and enables them more easily to communicate, learn, enjoy and live better, more independent lives (BATA, 2015, para.2).**

Learning Any Where; Learning Any Time

- Oxford University Press (2015)-a virtual learning environment (VLE) is for delivering learning materials to students via the web.
- These include Students' assessment, tracking, collaboration and communication tools.
- VLE are utilized for imparting informal and formal education.
- VLE is also often be referred to as -
  - Learning Management System (LMS),
  - Content Management System(CMS),
  - Managed Learning Environment (MLE) and
  - Learning Platform.
- Various institutions have developed e-learning systems which help educational programs across borders of time and space.
- The value of a virtual learning environment is to fully bring out the characteristics of both 'Learning Any Where' and 'Learning Any Time', i.e., learning in an asynchronous way.

Virtual Learning Environments (VLE)

- The virtual learning environments are utilized for not only imparting informal but formal education as well.
- A collaborative virtual learning environment is a computer-based, distributed, virtual space or set of places.
- In such places, people can meet and interact with others, with agents, or with virtual objects. Collaborative virtual learning environment might vary in their representational richness from 3D graphical spaces, 2.5D, and 2D environments to text-based environments.

Handbook of Research on Modern Educational Technologies, Applications, and Management. Copyright: © 2021

Current uses of VLE

Examples include the following and more:

- Distance Learning Degree Programs
- Professional Certification Courses
- Instructional Videos
- Video or Audio Lectures
- Books, Articles, and Other Writings
- Podcasts
- Webinars
- University Classes

The Future of Education and Technology

[Kali, B.(2019)]

The Future Of Education And Technology

- Recent advancements in EdTech field looms on the horizon of positive disruption and are amazing.
- New technologies make it easier and faster for students to learn.
- The developments are empowering educators to create remarkable learning experiences for young minds.
- A recent poll reveals that 75% of educators believe that digital content may replace textbooks by the year 2026.
- Choosing innovations to bring into the classroom will be a challenge for educators.

The Future Of Education And Technology

- Virtual Reality (VR) is one extraordinary technology deployed in the classroom.
- Mobile EdTech is another resource that's emerging in the field.
- Educators are also experimenting with gamification – a teaching resource that turns learning into a videogame. This tool entices learners by challenging them to complete work in order to reach a new level.
- Educational software (s) presents reading materials based on students' comprehension level.
- In addition, today's students have access to many part-time and certificate online learning programs. Not only are these resources available for K-12 learners, but they extend through university levels as well.

The AI-Driven Digital Transformation Of Learning And Development

Virtual Reality Emerging Tool in Education

Telepresence Robots for learning and teaching

Use of Blockchain Technology in eLearning Industry

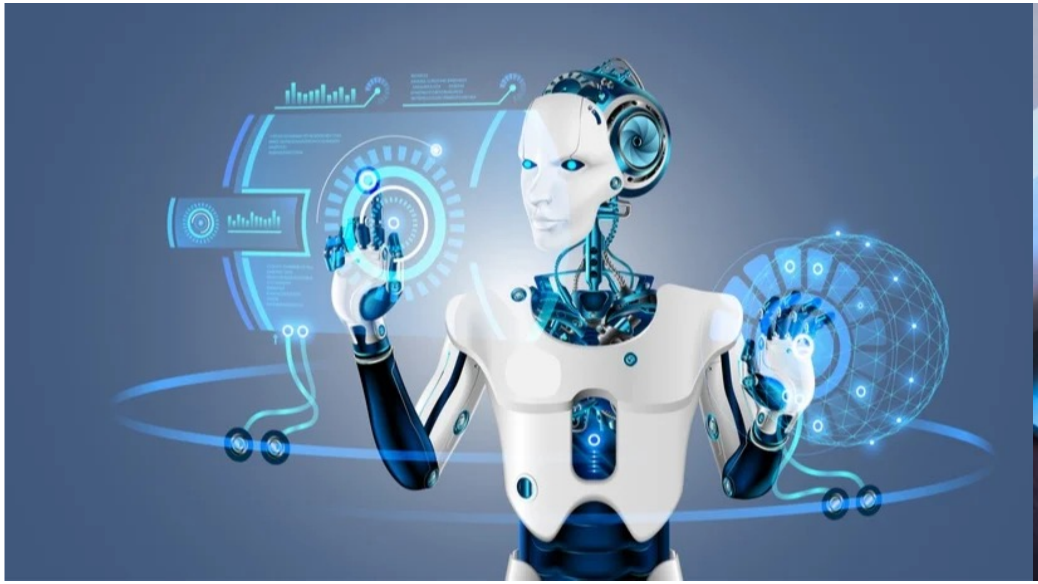

Emerging technologies in Education

- Artificial intelligence (AI, machine learning, cognitive computing)
- BioTech and informatics
- Blockchain (deep ledger technology)
- Internet of Things (IoT)
- Quantum technologies
- Robotics
- Smart classrooms
- Virtual/augmented/enhanced reality/human augmentation/immersion
- 3D printing and 3D printer materials (nanomaterials)
- 5G technology

These technologies are listed in alphabetical order and not by the level of impact.

Conclusions

- The use of information and communication technologies in education can play a crucial role in providing new and innovative forms of support to teachers, students, and the learning process more broadly. [The World Bank Group (WBG)]
- We must also transform how teachers interact with teaching materials and students.

Thanks a lot

Mob: +919414138211
ajeygahlot@gmail.com

संलग्नक–3

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा विषय	चर्चा के बिन्दु	निर्णय	विभाग/विश्वविद्यालय जिससे क्रियान्विति अपेक्षित है।
1.	गत कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 04.11.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	• सचिव, राज्यपाल द्वारा बताया गया कि कुलपति समन्वय समिति की गत बैठक दिनांक 04.11.2019 को आयोजित की गई थी, जिसका कार्यवाही विवरण दिनांक 19.11.2019 को जारी किया गया। चूंकि कार्यवाही विवरण के संबंध में कोई आपत्ति किसी प्रतिभागी से प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति जताई गई है।	प्रस्ताव स्वीकार एवं तद्नुसार दिनांक 19.11.2019 को जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जाता है एवं जिन विश्वविद्यालयों/विभाग द्वारा पालना नहीं की गई है, उनके द्वारा पालना सुनिश्चित की जाये।	–
2.	विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की रिक्तियों की स्थिति एवं भर्ती की कार्ययोजना के संबंध में।	• सचिव, राज्यपाल द्वारा सूचित किया गया कि विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27.12.2021 को विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत 5154 शैक्षणिक पदों के विरूद्ध 3089 पद रिक्त हैं एवं कुल स्वीकृत 9745 अशैक्षणिक पदों के विरूद्ध 5141 पद रिक्त हैं। • पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा अवगत	विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक/अशैक्षणिक रिक्त पदों से संबंधित प्रस्ताव अतिशीघ्र तैयार कर अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित करावें। जो विश्वविद्यालय अपने Resource से पदों को भरने में सक्षम हैं, उन्हें उन पदों को भरने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की जावे साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा यह भी सुनिश्चित	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग

		करवाया कि राज्य सरकार द्वारा उन्हे प्रोफेसर के पद स्वीकृत नहीं किये गये है। ● हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा पद स्वीकृत है लेकिन उन्हें यूजीसी के नये नियमों के अनुसार पत्रकारिता में Ph.D. की योग्यता होने के कारण आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे है। ● राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके दो विभाग CFCT/CIC में एक भी Faculty नहीं है। ● डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि 60 प्रतिशत पद रिक्त है।	किया जाए कि भविष्य में इन पदों से संबंधित किसी भी वित्तीय भार के लिए राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय दायित्व न आये। जिन विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से रिक्त पदों को भरने हेतु Fund अपेक्षित है, उन विश्वविद्यालयों की आगामी BFC में इस संबंध में चर्चा की जावे।	
3.	पेंशन प्रकरणों के संबंध में विश्वविद्यालय वित्तीय प्रबन्धन की समीक्षा, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबन्धन से संबंधित कई कठिनाइयाँ जिन्हें समुचित प्रबन्धन के	● कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 04.11.2019 में चर्चा के दौरान लिए गए निर्णयानुसार राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंशन व अन्य भुगतानों संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान किए जाने हेतु दिनांक 19.11. 2019 को कमेटी का गठन किया गया	कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रेषित की जाए।	वित्त विभाग एवं कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

	माध्यम से सुलझाये जाने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता एवं कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (सदस्य सचिव) के अन्तर्गत गठित कमेटी की प्रगति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।	है। • उक्त कमेटी की last Meeting दिनांक 22.07.2021 को आयोजित की गई।		
4.	कोविड–19 की विषम परिस्थितियों के मध्य नजर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया को पेपरलैस करते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल करने एवं परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन पद्धति में सुधार हेतु नवाचार की आवश्यकता तथा मूल्यांकन पद्धति को और अधिक त्वरित व कुशल बनाने के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में।	• प्रो. ए.के. गहलोत द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है कि SUMS के अंदर Pre-Admission से लेकर Degree तक के सारे Features होंगे एवं समस्त विश्वविद्यालय एक साल के अंदर SUMS लागू किया जाना सुनिश्चित करें। • साथ ही इन्होंने अवगत कराया कि वित्त विभाग ने SUMS बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है एवं नॉडल विश्वविद्यालय MLSU द्वारा Tender Invite कर लिया है एवं अंतिम Negotiation के पश्चात जनवरी, 2022 के प्रथम सप्ताह में MoU Sign कर लिया जायेगा। • शासन सचिव, कौशल विभाग द्वारा	SUMS की MoU संबंधी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए एवं समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय–सीमा में इसे लागू किया जाए।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों के बेरोजगार विद्यार्थियों का Database, Jan Aadhar को Integrate करके बनाया गया है। ● E-Employment Exchange Portal शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के आधार पर Job Seeker or Potential Employer के मध्य सेतु का काम करता है। ● इस Database के बनने से छात्रों की नौकरी के समय Document Verification or विदेश जाने पर भी Verification हो सकेगा।		
5.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा एल्युमिनाई से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु समय–समय पर एल्यूमिनाई मीट आयोजित करने के संबंध में।	● सचिव, राज्यपाल द्वारा समस्त कुलपतिगण को Virtual Alumni Meet आयोजित करने हेतु कहा गया। ● राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कमेटी का गठन कर दिया गया है एवं सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल कर भव्य आयोजन किया जायेगा। ● माननीय मंत्री श्री बी.डी. कल्ला द्वारा अवगत कराया गया कि Engineering College or Medical College में हर साल Alumni Meet होती है, जिसमें	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण को निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर Alumni Meet का आयोजन किया जाए एवं भामाशाहों से संपर्क स्थापित कर बौद्धिक, आर्थिक एवं रोजगार आदि के क्षेत्र में अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		भामाशाहों द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। ● अतः विश्वविद्यालयों को भी अपनी Alumni Meet में भामाशाहों को जोड़ना चाहिए। ● स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26.12.2020 को Virtual Alumni Meet आयोजित की गई थी जिसमें 25 देशों के Alumni जुड़े। ● अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षा विभाग में ऐसे बहुत से स्कूल है जिनमें भामाशाहों द्वारा आर्थिक योगदान किया जाता है। अतः विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण अपने विश्वविद्यालय से Pass Out हुए ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान में भामाशाह बन सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर Alumni Meet में आमंत्रित करें।		
6.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संरक्षण हेतु किये गये	● श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कैम्पस में स्थापित RWHS की क्षमता जो पहले 3 करोड़ लीटर थी,	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की तर्ज पर RWHS विकसित किया जाना सुनिश्चित करावें।	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य वित्त पोषित

	प्रयासों की वर्तमान स्थिति।	को बढ़ाकर 29.5 करोड़ लीटर कर दिया गया है एवं Severage Treatment Plant के द्वारा 1 लाख लीटर प्रतिदिन पानी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है तथा विश्वविद्यालय में 11 करोड़ लीटर का तालाब है।		विश्वविद्यालय
7.	विश्वविद्यालयों में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए विशेष बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।	• राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में बी.एड स्पेशल कोर्स चलाए जा रहे हैं। • महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांग विभाग एवं शिक्षक की आवश्यकता है। • मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि इससे संबंधित 10 कोर्स Rehabilitation Council of India को प्रेषित किए जा चुके है। शीघ्र ही अनुमति मिल जाएगी। • कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके संबद्ध कोटा एवं झालावाड कॉलेज में पाठयक्रमों का संचालन किया जा रहा है।	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए विशेष बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में Nodal Officer नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।	कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
8.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान	• राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासनिक एवं	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

	पार्क एवं विश्वविद्यालय पार्क की स्थापना की वर्तमान स्थिति।	वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। शिलान्यास के बाद कार्य पूरा कर लिया जायेगा। • हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य इस महीने पूरा हो जायेगा। • महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 20 दिन में तैयार हो जायेगा। • श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया कि जमीन चिन्हित कर ली गई है, शीघ्र ही शिलान्यास कर लिया जायेगा। • सचिव, राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित किया गया कि कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अन्य कुलपतिगण को संविधान पार्क देखने हेतु अपने यहां आमंत्रित किया जाए।	परिसर में संविधान पार्क/संविधान स्तम्भ बनाया जाना अनिवार्य है। शीघ्र ही पालना कर पालना रिपोर्ट राजभवन को प्रेषित करावें। साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा राजभवन में विश्वविद्यालय पार्क भी आवश्यक रूप से यथाशीघ्र स्थापित किया जाए।	
9.	समान विषय में समान पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम अद्यतन – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुकूलन में पाठ्यक्रमों में समानता तथा पाठ्यक्रमों को अनवरत	• सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों द्वारा UPSC की तर्ज पर पाठयक्रमों को अद्यतन किया जाए। • माननीय मंत्री श्री बी.डी. कल्ला द्वारा अवगत कराया गया कि UPSC के	विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

	अद्यतन करना एवं Choice Based Credit System का क्रियान्वयन करने के संबंध में कार्य योजना।	Pattern के आधार पर समस्त विश्वविद्यालयों में समान पाठयक्रम हो जिससे राजस्थान के युवा सिविल सर्विसेज आदि में जा सके।		
10.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने के संबंध में।	● सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों में जो भी कुलसचिव लगाए जाएं उनका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का हो। ● विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों में वित्त नियंत्रक के रिक्त पदों पर प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिए गए हैं। ● अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पदस्थापन हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से आवेदन मांगे जाने चाहिए। ● सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कुलसचिव व वित्त नियंत्रक दो स्थानों का कार्यभार होने के कारण अपना पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं। इस हेतु विश्वविद्यालयों में कैडर/पैनल बनाकर सक्षम स्तर से	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा बताया गया कि कुलपतियों एवं कुलसचिवों के मध्य सामंजस्य नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक शिकायतें होती हैं जिसके कारण स्थानान्तरण होते हैं। जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य अनावश्यक बाधित होते हैं तथा विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है। अतः कार्मिक/वित्त विभाग इस ओर विशेष ध्यान देवें जिससे कुलपतियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य असामंजस्य की स्थिति न बने। साथ ही कुलसचिव व वित्त नियंत्रक का पदस्थापन कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाए।	कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग

		अनुमोदन पश्चात विश्वविद्यालय के ही अधिकारी को कुलसचिव के पद पर नियुक्ति दी जाए। ● महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलसचिव का पद हो। ● श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा अवगत कराया गया है कि कुलसचिव द्वारा अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है। जिसके लिए उनके द्वारा भारी नाराजगी व्यक्त की गई है। ● जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि उत्तर प्रदेश की प्रथा लागू की जावे, जहां सहायक कुलसचिव, उप कुलसचिव एवं कुलसचिव की कैडर पोस्ट है जो स्थानान्तरण योग्य है। ● जग्‌दगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अल्प समय के लिए कुलसचिव का पदस्थापन किया जाता रहा है और वर्तमान में पदस्थापित कुलसचिव को		

		अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अतः वर्तमान कुलसचिव का अतिरिक्त कार्यभार हटा दिया जाए एवं पूर्णकालिक किया जाए।		
11.	प्रदेश स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय क्रीडा एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन– प्रदेश स्तर पर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव का कलैण्डर बनाकर आयोजन किया जाना तथा स्पोर्ट्स को स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित करना, जिसमें राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं गैर सरकारी विश्वविद्यालयों की सहभागिता हो।	• माननीय मंत्री श्री बी.डी. कल्ला द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयों में Inter University Level पर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। इससे देशाटन व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।	विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
12.	विश्वविद्यालय में केन्द्रीयकृत शोध एवं शैक्षणिक केन्द्र स्थापित कर संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को शोध एव शैक्षणिक उन्नयन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने बाबत।	• राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा शोध सेन्टर स्थापित किए जा चुके हैं। • बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा पांच का प्रस्ताव भेजा हुआ है।	विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त निजी/राजकीय महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को भी शोध हेतु शामिल किया जाए।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		• डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा पंचकर्म का प्रस्ताव रखा गया है।		
13.	विश्वविद्यालयों के बकाया अंकेक्षण आक्षेप (Audit Para's) की स्थिति व उनके प्रभावी निस्तारण हेतु कार्ययोजना यथा :– अंकेक्षण आक्षेप (Audit Para's) के निस्तारण हेतु कैम्पों का आयोजन कर निस्तारित करवाना।	• विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा 27 विश्वविद्यालयों के ऑडिट का कार्यक्रम जारी किया गया जिसमें 19 विश्वविद्यालयों की ऑडिट पूरी हो गई है। ऑडिट में विश्वविद्यालयों के 153 पैरा पेंडिंग है और 38 के जवाब प्राप्त हो गए हैं।	विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
14.	विश्वविद्यालयों द्वारा विशिष्ट पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं हेतु देश एवं विदेश में विश्वविद्यालयों में Student Exchange Programme की दिशा में पहल करना तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित छात्रवृत्ति योजना ''Rajeev Gandhi Scholarship for Academic Excellency Yojana – 2021'' के तहत छात्र/छात्राओं का अधिक से अधिक संख्या में विदेश	• आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि यह इस योजना का प्रथम वर्ष है। इस योजना में 8 लाख से कम आय वाले विद्यार्थियों को 150 अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेता है तो राज्य सरकार द्वारा उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। • वर्तमान में 200 बच्चों तक इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में अब तक केवल 36 ही आवेदन प्राप्त होने के कारण इसमें आवेदन की अंतिम दिनांक 31.12.2021 निर्धारित की गई है।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में Eco System विकसित किया जाए जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जा सके।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

	में रिसर्च एवं उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करना।	● चूंकि विश्वविद्यालय का नया सत्र फरवरी, 2022 में शुरू होगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में Eco System विकसित किया जाए जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जा सके।		
15.	स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के तहत, कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालयों के अधीन पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर गोपालन, गोकास्ट, दीपक एवं गाय के गोबर से पेन्ट बनाये जाने की संभावनायें तलाशना। महिला स्वयं सहायता समूह का गठन कर, क्षेत्र विशेष के कुटीर उद्योगों की तलाश करने की दिशा में प्रयास करना तथा स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के तहत संबंधित ग्राम को राजसमंद स्थित ''पिपलांत्री'' गांव की तर्ज पर वृक्षारोपण व जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया जाना।	● माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा बताया गया कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा गोद लिए गए मदार गांव द्वारा किए गए नवाचारों की तरह अन्य विश्वविद्यालय भी अपने गोद लिए गांवों में महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करें। जिससे महिलाओं के लिए छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले।	विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

16.	आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अब तक सम्पन्न करवायी गयी कृतियों/कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा तथा अमृत महोत्सव के परिपेक्ष्य में आगामी वर्ष में आयोज्य संगोष्ठी व कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों व विद्यार्थियों को आजादी के मूल्यों को स्थापित करने के संबंध में कार्ययोजना बनाना।	• आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्थानीय/राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की लडाई में किस–किस ने भाग लिया एवं किस–किस ने योगदान दिया के संबंध में प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा कृतियों कार्यक्रमों/संगोष्ठी/कार्यशालाओं के माध्यम से अभियान चलाकर युवाओं को आकर्षित करें, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग का भी सहयोग लिया जा सकता है।	विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय